P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-11* July- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं रोजगार : समस्या एवं समाधान

सारांश

भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार, प्राचीन काल से ही ग्रामीण कृषि एवं गैर कृषि कार्य रहा है। कृषि व्यवसाय, ग्रामीणों की आय का सबसे बड़ा स्रोत, रोजगार एवं जीवन यापन का प्रमुख साधन, ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योग का आधार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ तथा विकास की कुंजी है। कृषि आधारित उद्योगों का राष्ट्रीय आय में 46 प्रतिशत योगदान है और लगभग 70 प्रतिशत श्रमिक गॉवों में रहता है। उद्योग व घरेलू जरूरतों पर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए प्रशिक्षित हुनरमंदों (कौशल विकास) की आबादी बढ़ायी जाय, जो हर मौके पर रोजगार तलाश करने के बजाय खुद का रोजगार पैदा करने में सक्षम हो जाए। खुद रोजगार खड़ा करें और अन्य बेरोजगारों के लिए अवसर बन जाय। हमारी चुनौती है कि अधिकतर निर्धन देशवासी, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते है जिन्हें मूलभूत आवश्यकताएं भी सुलभ नहीं हो पाती है। उनकी समस्या का समाधान खोजना है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं रोजगार से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। देश के आर्थिक विकास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के योगदान पर विस्तृत विवेचन किया गया है।

मुख्य शब्द : ग्रामीण विकास, कृषि उद्योग, अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास, कौशल विकास, रोजगार इत्यादि।

विनोद कुमार
सहायक प्रोफेसर,
अर्थशास्त्र विभाग,
राजकीय महाविद्यालय
पिपरहरी, तिन्दवारी,
बाँदा, उत्तर प्रदेश

प्रस्तावना

विभिन्न आर्थिक सुधारों से देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयास किए गये है। आर्थिक नीति का प्रमुख उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। भारत में लगभग 6.5 लाख गाँव है और देश की 1.25 करोड़ जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत आबादी गाँवों में निवास करती है। जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि ग्रामीणों की आय का सबसे बड़ा स्रोत, रोजगार एवं जीवन यापन का प्रमुख साधन, ग्रामीण उद्योगों का आधार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ तथा विकास की कुंजी है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दो भाग (1) कृषि क्षेत्र तथा (2) गैर कृषि क्षेत्र। अधिकांश ग्रामीण लोगों का ध्यान गैर कृषि की ओर आकर्षित हो रहा है जहॉ रोजगार के अधिक अवसर विद्यमान है। कृषि का आधुनिकीकरण तथा वाणिज्यीकरण, गैर फसल वस्तुओं एवं सेवाओं की बढ़ती हुई मांग शहरीकरण, बढ़ती साक्षरता तथा कल्याण उन्मुख नीति, बढ़ती बेरोजगारी आदि, विकासात्मक कार्यक्रम तथा योजनाएं श्रम शक्ति को कृषि क्षेत्र से हटाकर गैर कृषि क्षेत्र की ओर ले जाने की कोशिश की है। रोजगार सृजन विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना, भारतीय नियोजन का प्रमुख उद्देश्य रहा है। निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या तथा लगातार घटते रोजगार अवसरों के सन्दर्भ में कृषि सम्बद्ध क्रियाओं के क्षेत्र में अधिकाधिक रोजगार सृजन करना वर्तमान की आवश्यकता है।

ग्रामीण विकास

अर्थव्यवस्था के विकास का वह घटक जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वागीण विकास में पिछड़ा है। ग्रामीण भारत के विकास के लिए जिन क्षेत्रों में नई और सार्थक पहल करने की आवश्यकता बनी हुई है, वे इस प्रकार है।

1. महिला शिक्षा, कौशल विकास एवं तकनीकी प्रगति।
2. मानव विकास सूचकांक, स्वच्छता।
3. प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादक संसाधनों का विकास, भूमि सुधार।

4. आधारभूत संरचना का विकास जैसे–बिजली, सिचाई, साख, विपणन, परिवहन सुविधाए, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, कृषि अनुसंधान विस्तार और सूचना प्रसार की सुविधाए।
5. गरीबी उन्मूलन और समाज के कमजोर वर्गों की जीवन दशाओं में सुधार के विशेष उपाय, जिसमें उत्पादक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
6. समाज का कैंसर–जाति प्रथा, सम्प्रदाय, धर्मान्धता, छुआछूत इत्यादि का समूलनाश किया जाना चाहिए जिससे समाज में समानता एवं आपसी सहयोग की भावना का विकास हो सके।

अतः ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो कृषि एवं गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न है, उन्हें उत्पादकता बढ़ाने में विशेष सहायता देनी होगी ताकि तेज गति से ग्रामीण विकास हो सके।

अध्ययन का उद्देश्य

1. कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन की क्षमता का परीक्षण करना।
2. ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की प्रवृत्तियों एवं प्रकृति का विश्लेषण करना।
3. वैश्वीकरण, उद्यरीकरण एवं निजीकरण का ग्रामीण रोजगार पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन
4. रोजगार विविधिकरण का समाज के कमजोर वर्गो के रोजगार अवसरों का विवेचन
5. रोजगार सृजन में मशीनों के प्रयोग का अध्ययन
6. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु सुझाव प्रस्तुत करना
7. ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं एवं चुनौतियों का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार विविधिकरण के सन्दर्भ में पुराना एवं नवीनतम सामग्री जुटाने का प्रयास किया गया है। इस कार्य में वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक विधियों का प्रयोग किया गया है। तथ्यों के संकलन हेतु द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। द्वितीयक समंकों के लिए शोध पत्रिकाएं, शोध आलेख, विषय से संबंधित पूर्व शोध अध्ययन, जर्नल्स, समाचार पत्र, अध्यादेश अधिनियम, इण्टरनेट आदि का प्रयोग किया गया है।

साहित्यावलोकन

''स्माल इज ब्यूटीफूल'' के लेखक *ई0एफ0 सुमाखर* एक ऐसी टेक्नालाजी को प्रयोग में लाने की बात करते है जो उन दशाओं के लिए उचित हो जो गांवो में रहते है तथा जो इतनी सरल हो कि जिनके पास उच्च प्रशिक्षण तथा शिक्षा का अभाव है, उन लोगों द्वारा अच्छी तरह समझी जा सकें तथा प्रयोग में लायी जा सकें, ऐसी कम लागत वाली टेक्नीक जिनमें कम पूंजी लगे तथा जो ऐसे यत्र तथा संयन्त्र को प्रयोग में लाये जो सस्ते हो पर साथ ही कुशल तथा कम कठिनाई उत्पन्न करने वाले हो तथा जो स्थानीय कच्चा माल की पूर्ति तथा छोटे स्तर पर विपणन के अनुरूप हों, ऐसी टेक्नालाजी को सुमाखर इण्टरमीडिएट टेक्नालाजी कहते है।

प्रो0 हर्षमैन ग्रामीण अवस्थापना के विकास की बात करते है। अवस्थापना के दो रूप है, भौतिक तथा सामाजिक है जिसकों हर्षमैन सामाजिक उपरिव्यय पूँजी कहते है। भौतिक के अन्तर्गत निम्नांकित को सम्मिलित किया जाता है। (1) यातायात (2) संवहन (3) शक्ति। इन तीनों के अतिरिक्त अवस्थापना में हम विज्ञान तथा टेक्नालाजी बैंकिग, बीमा तथा वित्तीय संस्थाओं के विकास तथा सूचना प्रणाली को भी सम्मिलित करते है जो आर्थिक विकास के लिए आधार तैयार करते है। भौतिक अवस्थापना अग्रगामी तथा पार्श्वगामी श्रृंखलाओं के द्वारा आर्थिक विकास को सुगम बनाती है। सामाजिक अवस्थापना जिसमें जल आपूर्ति, सफाई तथा सीवेज, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्मिलित करते हैं, प्राथमिक सेवाओं के समान हैं तथा इनका जीवन की गुणवत्ता तथा मानवीय पूंजी की उत्पादकता की वृद्वि पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

डा0 अम्बेडकर के अनुसार जाति का एक आर्थिक पक्ष है और जातिप्रथा के उन्मूलन के लिए, भारतीय गांवो की आर्थिक संरचना का पुनर्गठन आवश्यक है। भारत की आबादी का लगभग 70 प्रतिशत कृषि पर निर्भर है और गांवो में रहता है, जहां जातिवाद और सांप्रदायिकता का बोलबाला है। इसलिए उन्होने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा, '' मेरा मानना है कि ग्रामीण गणतंत्र भारत का विनाश कर देगें। गॉव, स्थानीयता की नाली और अज्ञानता, संकीर्ण सोच और सांप्रदायिकता के अड्डों के अलावा क्या है? मुझे प्रसन्नता है कि संविधान के मसविदे में गांव की जगह व्यक्ति को इकाई बनाया गया है।'' उनकी यह मान्यता थी कि अगर गांवों को उनकों बुराईयों से मुक्त किया जाना है तो कृषि क्षेत्र में आधुनिक परिवर्तन लाने होगें। उनका कहना था कि गांव की वर्तमान व्यवस्था न केवल जातिप्रथा की पोषक है वरन कृषि के विकास में भी बाधक है। उनका कहना था कि ऊँची जाति के हिन्दू न तो स्वंय खेंत को जोतेंगे और न ही उसे किसी ऐसे व्यक्ति को हस्तांतरित करेंगे, जो उसका बेहतर उपयोग कर सके। इसलिए कृषि भूमि का राष्ट्रीयकरण, जातिप्रथा की रीढ़ तोड़ देगा और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देगा, जिससे उद्योगों के लिए 'विपणन योग्य अतिशेष' उपलब्ध हो सकेंगा।

भारत में 'दलित वर्गों' को आर्थिक स्वतंत्रता उपलब्धता नहीं थी। उनके पास न तो जमीन थी, न सामाजिक हैसियत, न व्यापार–व्यवसाय में हिस्सेदारी और ना ही सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व। इसलिए अम्बेडकर ने उद्योग के क्षेत्र में 'राज्य समाजवाद' की वकालत की और कृषि भूमि पर राज्य के मालिकाना हक और सामूहिक खेती पर जोर दिया। '' उनका यह दृढ़ मत था कि भूमिहीन श्रमिकों की समस्या का निदान चकबंदी या बटाईदारों को भूमि पर मालिकाना हक देने मात्र से नहीं होगा। केवल खेतों पर सामूहिक स्वामित्व से यह समस्या हल हो सकती है'' (बी0आर0 अम्बेडकर : लाईफ एंड मिशन, 1961)।

अमर्त्यसेन के अनुसार भारत का वह भाग है जहां '' भारत की 75 प्रतिशत जनसंख्या लगभग साढ़े छः

लाख दूर–दूर के गावों में निवास करती है, जहां देश को 91 प्रतिशत गरीबी, 90 बेरोजगारी और इससे अधिक अनूपात में अशिक्षा, कुपोषण एवं पिछड़ापन है। देश की सत्ता, साधन व तमाम चमक–दमक का प्रतिबिम्ब राजधानियॉं– दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास व बग्लौर आदि शहरों में देखा जा सकता है। लोकतंत्र का ''लॉक'' ग्रामीण भारत में बसता है ''तंत्र सार'' शहरों में सिमट गया है। 'लॉक' अभी भी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है। इसलिए सबसे पहले देश के लॉक का इस विसंगति व भेदभाव पूर्ण स्थिति की जानकारी देकर उन्हें चेतन किया जाना जरूरी है। भारत गांवों का देश है, यहां की आत्मा गांवों में निवास करती है। महात्मा गांधी जी का कथन है कि ग्रामीण अंचलो का विकास किए बिना भारत विश्व आर्थिक विकास की दौड़ में अग्रणी नहीं हो सकता।

एम0एल0 दंतुलाल (1979) : ''ग्रामीण रोजगारः प्रभाव और उपकरण'' ने शोध पत्र पर इस बात पर जोर दिया की कोई भी रोजगार देने की योजना इस तथ्य पर आधारित होती है कि बेरोजगारी के कारण व प्रकार क्या है एवं इन्हें सामाजिक, आर्थिक, संरचनात्मक असमान विभागीय रूप रेखा के मूल कारणों पर आधारित होती हैं। यहॉं पर बेरोजगारी की दशा के दो या तीन मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई एवं बेरोजगारी की घटनाओं तथा श्रमशक्ति के परस्पर संबंधों पर प्रकाश डाला गया है।

आर0 एवं स्टेवर्ट (1993) : ने अपने अध्ययन में विविधिकरण की ओर हमारा ध्यान केन्द्रित किया है। रोजगार विविधिकरण विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है। विशेषरूप से एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका देशों में। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में विविधता कृषि की अपेक्षा गैर कृषि में अधिक देखने को मिलती है। शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर आर्थिक विकास तथा तकनीकि प्रगति के साथ रहे है परन्तु वर्तमान परिदृश्य में गैर कृषि क्षेत्र ही ग्रामीण रोजगार में विस्तार तथा विविधिकरण का आधार हो सकता है इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार तथा गरीबी समस्या का हल हो सकता है।

जी0के0 चट्ड़ा (2002) : ने ग्रामीण गैर कृषि रोजगार में काफी सारी कठिनाईयाँ देखी है, परन्तु विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए ज्यादा कष्टदायक रही। यातायात, संग्रह, व्यवहार संदेश निर्माण और कुछ हद तक कारीगरी इत्यादि ऐसे कुछ क्षेत्र है, जहॉं से संतुष्टि मिली। जबकि फुटकर तथा विशेषकर थोक व्यापार, आर्थिक संग्रह, बीमा, सामाजिक, व्यक्तिगत सेवाएं और तो और कृषि क्षेत्र में भी एक प्रकार का उतार चढ़ाव नजर आया। राज्यों के हिसाब से भी एक मिश्रित परिणाम देखने को मिला है जो दोनों तरफ झुका है। कुल मिलाकर ग्रामीण रोजगार विकास दर बड़े–बड़े 17 राज्यों में से 13 मे गिरावट देखी गयी है।

वही गैर कृषि क्षेत्र में 11 राज्यों में गिरावट देखा गया और कारीगरी क्षेत्र में 8 राज्यों में। इस अध्ययन में सभी राज्यों में रोजगार विविधताओं का पता लगाने की कोशिश की गयी है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल आदि राज्यों ने कुछ वायदों के साथ कहा कि वे ग्रामीण कारीगरी क्षेत्रों में बढ़ोतरी करेगे और उससे जुड़ी अन्य गतिविधियों के होस्ट भी बनेंगे।

रंजन शरद (2006) : ने अपने अध्ययन में ग्रामीण विकास की गति तीव्र करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने आय और उत्पादकता में वृद्धि करने, गरीबी उन्मूलन तथा नगरों की ओर पलायन हेतु गैर कृषि गति विधियों में विस्तार को रेखांकित किया है। महत्वपूर्ण है कि कभी रोजगार का प्रमुख माध्यम न रहने वाला गैर कृषि क्षेत्र, वर्तमान में ग्रामीण विकास का प्रमुख यंत्र कहा जाने लगा है। अपने शोध में कृषि क्षेत्र तथा ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के मध्य सैद्धांतिक अन्तसंबंधों का परीक्षण किया है साथ ही गैर कृषि क्षेत्र में विविधिकरण के कारकों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

भाटिया संदीप कौर (2009) : ने पंजाब की अर्थव्यवस्था से संबंधित अध्ययन में यह विश्लेषित किया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार तथा उत्पादन में विविधिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सतत विकास के लिए अनिवार्य है। प्रस्तुत विश्लेषण में गैर कृषि रोजगार का परीक्षण करते हुए निष्कर्ष प्राप्त किया है कि पंजाब के समस्त जिलों में गैर कृषि रोजगार की मात्रा तथा अनुपात दोनों बढ़ा है। परन्तु विभिन्न जिलों के मध्य गैर कृषि रोजगार में असमानता भी है। साक्षरता इसका सबसे मुख्य कारण रहा है। अमृतसर, फरीदकोट कपूरथला के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि रोजगार की क्षमता सीमित है। अतः इन जिलों में गैर कृषि क्षेत्र में राज्य *'पुश'* फैक्टर के कारण है। अतः ऐसी नीतियों तथा कार्यक्रमों की आवश्यकता है कि *'पुल'* फैकटर के कारण, रोजगार विविधिकरण होना चाहिए। गैर कृषि रोजगार न केवल प्रति व्यक्ति आय पर केन्द्रित हो अपितु रोजगार विशेषकर शिक्षित युवाओं की अपेक्षाओं के अनुकूल हो।

डॉ0 रहीस सिंह (2016) : भारतीय युवाओं में जिस मनोविज्ञान का निर्माण हुआ है। अथवा किया गया है, उसके केन्द्र में नौकरी है, उद्यम नहीं। जबकि वास्तविक राह उद्यमिता के विकास से ही होकर जाती है। इसलिए आज की जरुरत यह है कि हमारा युवा वर्ग एक सफल उद्यमी बनने का मनोविज्ञान विकसित करें या स्वप्न देखे ताकि वह स्वयं रोजगार तलाश न करें बल्कि रोजगार पैदा करें। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ऐसी उद्यमिता संभावनाएं ग्रामीण युवाओं में विद्यमान है? क्या ग्रामीण युवा कुशलता और तकनीक के स्तर पर शहरी युवाओं से प्रतियोगिता कर पायेगा?

डॉ0 जगदीप सक्सेना (2017) : हमारे देश में कृषि आज भी देश की अर्थव्यवस्था और उन्नति–प्रगति का आधार है जबकि करोड़ों किसान इसके सूत्रधार–कर्णधार है। किसानों के आर्थिक उद्धार को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए प्रधानमंत्री ने सन् 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया। अभी तक कृषि विकास का मुख्य उद्देश्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाना था। लेकिन नए नजरिए में कृषि को किसानों के लिए लाभकारी बनाना भी शामिल किया गया, जिससे

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-11* July- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

उनका सामाजिक–आर्थिक उद्वार हो और कृषक समुदाय संपन्नता के साथ सामाजिक सुरक्षा भी हासिल कर सके।

निमिष कपूर (2018) : देश में तकनीकी ज्ञान के विकास और विस्तार में वैज्ञानिकों के साथ ही देश के आम नागरिकों को भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। अपने पारंपरिक ज्ञान और बौद्धिक क्षमताओं में इजाफा करके एक किसान या किसी सुदूर गॉव में रहने वाला एक आम व्यक्ति भी अपने तकनीकी नवाचार से देश को समृद्ध कर रहा है। अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान–भारत द्वारा आम नवाचार को तकनीकी सृजन को विज्ञान की प्रयोगशाला और उद्योग तक पहुंचाकर प्रौद्योगिकी का रूप दिया जा रहा है। आम नवाचारको द्वारा ऐसी तकनीकों का विकास किया जा रहा है जो ग्रामीण भारत की दशा और दिशा उन्नति की ओर ले जा रही है। नवाचार को अर्थतंत्र का सारथी माना जाता है। आज ग्रामीण भारत में नवप्रवर्तन तकनीकों के स्टार्टअप की संभावनाएं बढ़ती जा रही है।

ग्रामीण विकास की समस्याएँ

1. हमारी आर्थिक प्रगति की दर 6 से 8 प्रतिशत के आस–पास रही है परन्तु गॉवों एवं वंचित वर्गो को इसका लाभ नहीं मिला है।
2. गॉवों में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, महिलाओं पर अत्याचार, जमीन के झगड़े, कम उत्पादन व उत्पादकता की समस्या।
3. प्राकृतिक विपदायें जैसे–बाढ़, सूखा, तूफानी हवायें, मृदा की नंपुसकता, पानी का अभाव इत्यादि। भारत के लगभग 20 से 25 राज्य हर वर्ष प्राकृतिक विपदाओं की मार झेलते है। जैसे असम, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश इत्यादि।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं की भारी कमी है।
5. गॉवों में शिक्षा का अभाव है जिसके परिणामस्वरूप गरीबी के कुचक्र को तोड़ नहीं पाते है।
6. ग्रामीणों के पास आधुनिकतम उपकरणें का अभाव है। कुछ राज्यों पंजाब, हरियाण, उत्तर प्रदेश इत्यादि को छोड़ शेष भारत में आधुनिक उपकरणों की कमी है।
7. गॉवों में आधार भूत संरचाओं का अभाव है।
8. गॉव से शहरों की ग्रामीणों का पलायन।
9. कर्ज के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आत्महत्या की समस्या। पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आत्महत्याओं के कई मामले प्रकाश में आये है।
10. ग्रामीण समाज में जातिवाद गंभीर समस्या है और उसका कारण गांवों की विभिन्न जातियों की सत्ता में प्रभावी भागीदारी न होना है। अप्रभावी पंचायती राज के कारण गॉवों में जातिवाद की समस्या बढ़ी है।
11. भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव है।
12. मनोरंजन के साधनों का अभाव है।

ग्रामीणों के विकास में सरकारी प्रयास

हमारे प्रधानमंत्री मा0 नरेन्द्र मोदी जी का स्वप्न नए और सशक्त भारत के निर्माण का रास्ता गॉवों, किसानों और खेत–खलिहानों से होकर गुजरता है। सरकार गांवों और किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होगी जब देश की विशाल आबादी, जिस कृषि पर निर्भर है उस पर आधारित आर्थिक तंत्र अपने पैरों पर खड़ा हो सके। वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार तथा स्वरोजगार के माध्यम से लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया जाय और सभी नागरिकों के कल्याण हेतु बुनियादी ढाचे में सुधार किया जाय। सरकार ऐसा विकास चाहती है जिसमें सभी को साथ लेकर चला जाय। चूंकि उसी के माध्यम से स्थायी प्रगति संभव है। सामाजिक समानता के उद्देश्य को लेकर सरकार मई 2018 तक सभी के लिए बिजली, 2022 तक सभी के लिए आवास, 2030 तक हर घर में जल का सकल्प लेकर चल रही है। साथ ही खाद्य उत्पादकता बढ़ाने के साथ–साथ 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

वित्तीय समावेशन के लिए *जनधन योजना* के अन्तर्गत लगभग 30 करोड़ नए गरीबों के बैंक खाते खाले गये है। यह वित्तीय समावेशन गतिशील कृषि अर्थव्यवस्था का केन्द्र है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लाखों परिवारों के जीवन में बदलाव आ रहा है। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत *'हर खेत को पानी' हर बूंद अधिक फसल'* के लक्ष्य के साथ सिंचाई को उच्च प्राथमिकता दी है। उधर *मृदा स्वास्थ्य कार्ड* से किसानों को खाद का उचित प्रयोग करने में मदद मिल रही है। *राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नैम)* से कृषि विपणन में ऐतिहासिक सुधार आयेगे। एक बार पूरी तरह चालू होने के बाद बाजार में विकृतियां खत्म हो जायेगी और किसानों को बेहद पारदर्शी तरीके से अपने उत्पाद की वाजिब कीमत मिल सकेगी। प्रधानमंत्री *फसल बीमा योजना* भारतीय किसानों को मौसम की मार से बचने में मदद करेगी और उन्हें मुश्किल समय में आय सुरक्षा प्रदान करेगी।

कृषि भूमि की स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाने के लिए मृदा जांच और नीम लेपित यूरिया, कृषि क्रांति की दिशा में प्रमुख कदम है। इस दिशा में अन्य कदम बांध निर्माण, जलाशयों और अन्य जल संरक्षण विधियों के जरियें जल संरक्षण, भू–जल स्तर बढ़ाना, टपक सिंचाई को बढ़ावा देकर पानी की बर्बादी कम करना, मृदा की उर्वरता का अध्ययन कर फसलों के तरीकों में बदलाव करना, पानी की उपलब्धता और बाजार की स्थिति है। विद्युतीकरण, पंचायतों में कंप्यूटरीकरण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए सड़क निर्माण के माध्यम से प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने से जमीनी स्तर पर विकास सुनिश्चित होगा। सड़क निर्माण से प्रत्येक गॉव के लिए बाजार और इन्टरनेट सम्पर्क उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।

मनरेगा आज लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा बन गया है। मिशन जल संरक्षण, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर मनरेगा के तहत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संबंधित कार्यो के लिए योजना और निगरानी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और इनके लिए वैज्ञानिक नियोजन, प्रभावी निगरानी, बढ़ी हुई दृश्यता और अधिक पारदर्शिता के लिए मनरेगा के तहत बनायी गई सभी संपत्तियों की

भू–टैगिंग के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है।

युवाओं के लिए सरकार आसान बैक ऋण, राजकोषीय रियायतों और प्रौद्योगिकी समर्थता की मदद से उद्यमशीलता बढ़ा रही है। युवाओं में स्वरोजगार की भावना पैदा करने के लिए और उन्हें अपने बूते आगे बढ़ने में मदद देने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे है। साथ ही, कौशल विकास और ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार कारगर उपाय कर रही है। डिजिटल पहल भीम, फाइबर आप्टिकल्स, बिक्री स्थलों और माल प्लेटफार्म जैसे परिचालन रूप तैयार करने के लिए कई पहल हेतु बुनियादी सहायता दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के उप जिले और 1.93 लाख से अधिक गॉव खुले में शौचमुक्त हो चुके है। यदि इसी गति से विकास कार्य होते रहे तो उम्मीद है नए भारत के निर्माण और ग्रामीण लोगों की जिदंगी बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित बड़े कार्यक्रम चलाये जा रहे है।

1. रोजगार देने के लिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्यायमेंट गारंटी एक्ट (मनरेगा)।
2. स्वरोजगार और कौशल विकास के लिए नेशनल रूरल लाइबली हूडस मिशन (एन0आर0एल0एम0)।
3. गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को आवास देने के लिए इंदिरा आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना।
4. अच्छी सड़के बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएम0जी0एस0वाई0)
5. सामाजिक पेंशन समाजिक सहायता के लिए नेशनल सोशल असिस्टेस प्रोग्राम (एन0एस0पी0)
6. आदर्श ग्रामों के लिए संसद आदर्श ग्राम योजना (एस0ए0जी0वाई0)
7. ग्रामीण विकास केन्दों के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन।
8. गांव का सामाजिक आर्थिक बदलाव करने के लिए मिशन अन्त्योदय योजना।
9. उज्ज्वला योजना इत्यादि।

उपलब्धियां

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 31 लाख से अधिक महिला स्व सहायता समूह और लगभग 3.6 करोड़ महिलाएं उस मिशन से जुड़ी हुई है। महिला स्वसहायता समूहों ने पिछले तीन वर्षो में 85000 करोड़ से अधिक का ऋण लिया है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2011–14 में प्रतिदिन 73.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ तो 2014–15 में प्रतिदिन 100 किलोमीटर सड़के बनी। 2016–17 में यह आकड़ा 130 किलोमीटर प्रतिदिन का था। 47350 किमी सड़क निर्माण से 11,614 बस्तियों को जोड़ा गया। प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्यों द्वारा 32.14 लाख घरो का निर्माण किया गया। 2016–19 को दौरान 1.35 करोड़ घरों के निर्माण का आकड़ा पूरा होगा। 2022 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य पूरा करना है। 2016–17 में मनरेगा ने 230 करोड़ दिन के बराबर रोजगार पैदा किये है। वैतनिक रोजगार में 56 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है। आधार आधारित पेमेट ब्रिज पर 4.6 करोड़ श्रामिक है, बैक/डाकघर खातों के माध्यम से 96 प्रतिशत मजदूरी का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में पानी से संबंधित 15.47 लाख काम पूरे किए गये जिनमें 56.6 लाख कृषि तालाब शामिल है। 2015–17 में मनरेगा के माध्यम से लगभग 90 लाख हेक्टेयर सिचाई क्षमता का निर्गाण किया गया है। डी0डी0यू0जी0के0 वाई और आर0एस0डी0टी0आई0 द्वारा बड़े पैमाने पर क्रमशः वैतनिक रोजगार आधारित प्लेसमेंट और स्वरोजगार के लिए कौशल विकास को बढ़ावा दिया गया है। उसके तहत 2016–17 में 1.60 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और 79400 को प्लेसमेंट मिला, जबकि 4 लाख युवाओं को रोजगार के लिए 585 'आर सेटी' में प्रशिक्षित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय 50,000 ग्राम पंचायतों, 5000 ग्रामीण समूहों में सभी परिवारों के लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना चाहता है जिसमें मूलभूत बुनियादी सुविधाए शामिल है। वर्तमान में 28 करोड़ से भी ज्यादा बैंक खाते जन–धन योजना के तहत खोले जा चुके है जिसमें से करीब 60 प्रतिशत ग्रामीण के है।

निष्कर्ष

ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं का एक बड़ा हिस्सा अशिक्षा और जागरूकता की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में, आज ऐसी राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता महसूस होती है, जो केवल ग्रामीण युवाओं की शिक्षा संबंधी स्थिति में सुधार लाने पर केन्द्रित हो। देश का प्रत्येक गॉव जात–पात की भावना से मुक्त हो जो डॉ0 अम्बेडकर जी का सपना था। जात–पात से मुक्ति के बिना देश, गॉव के समाज का विकास संभव नहीं है। हमारे देश में समावेशी और सतत विकास लाने के लिए, सामाजिक अवसंरचना जैंसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिका प्रदान की जा रही है। सरकार मानव संसाधन पर व्यय भी बढ़ाती रही है। रोजगार सृजन के अवसर पैदा करने तथा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में बड़े पैमानें पर कार्यरत जनता को स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए विधायी सुधार तथा श्रम सुधार के अनेक उपाय लागू किए जा रहे है। शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, आमदनी में स्त्रियों से जुड़े आनुपातिक अंतरालों का पाटना और समाज में व्याप्त सामाजिक विषमता (जाति प्रथा, ऊंच–नीच) को कम करना। मानव सामर्थ को संवर्धित करने की विकास परक कार्यनीति के मूल लक्ष्य रहे है। जिसे प्राप्त करना बाकी है।

वर्तमान सरकार द्वारा डिजिटाईजेशन और वित्तीय समावेशन, जेंडर को मुख्य धारा में लाने और भातीय समाज में अंतर्निहित सामाजिक असमानताओं के सभी स्वरूपों में कमी लाने से संबंधित उपायों के माध्यम से सामाजिक समावेशन प्राप्त करने के रूप में समावेशी विकास के लिए उतरोत्तर नीतियां और संस्थागत प्रणालियां तैयार की जा रही है जिससे आमजन जागरूक हो सके।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-11* July- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास–एन0सी0आर0टी0, 2014।
2. भारतीय अर्थ व्यवस्था सर्वोक्षक तथा विश्लेषण, लाल एवं लाल, 2013
3. भारतीय अर्थ व्यवस्था दत्त एवं सुन्दरर्भ, 2015
4. आर्थिक समीक्षा 2017–18 भाग–1 एवं 2
5. कुरूक्षेत्र – मार्च 2018, मई 2016, अगस्त 2018
6. अम्बेडकर : एवं हमदर्द अर्थशास्त्री–राजेश कुमार गौहर, 1 दिसम्बर 2015, फारवर्ड प्रेस।
7. ग्रामीण समाज की समस्याएं पर निबंध, रश्मि बी
8. ग्रामीण जीवन की तीन समस्याए–गरीबी, बिमारी एवं जातिवाद, किसान दैनिक–28.10.2017
9. ग्रामीण जीवन की समस्याएं–बेबसाइट लेखिका–स्नेहा दीपावली 20 जून 2016
10. ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट
11. http://m.vikashpedia.in/social.welfare/
12. मध्यप्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार विविधीकरण